

सरकार के लिए नहीं, बल्कि एक भारतीय नागरिक के रूप में विदेश दौरे में हुई शामिल-सुप्रिया सुले

पहलगाम हमले के संदर्भ में कहा-आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ मजबूती से खड़े हैं



रिपोर्ट: जमीर काज़ी, मुंबई
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) की राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष और सांसद सुप्रिया सुले ने गुरुवार को स्पष्ट किया कि वे किसी सरकार का प्रतिनिधित्व करने नहीं, बल्कि एक भारतीय के तौर पर विदेश दौरे पर गई थीं। उन्होंने यह भी कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ भारत सरकार के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। सुप्रिया सुले हाल ही में कतार, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और मिस्र के दौरे से लौटी हैं। मुंबई में पत्रकारों से बात

करते हुए उन्होंने कहा कि इस बहुदेशीय शिष्टमंडल का उद्देश्य भारत की ओर से शांति और सहिष्णुता का संदेश देना था। उन्होंने बताया कि विदेशों में हुई हर बैठक में वहां के नेताओं ने महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, डॉ. मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी जैसे नेताओं के योगदान की सराहना की। यह हमारे लिए गर्व की बात थी कि भारत का ७५-७६ वर्षों का विकास सफर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि विदेशों में भारत से बहुत सारी उम्मीदें हैं। आतंकवाद के मुद्दे पर वहां के नेताओं ने एक सुर में कहा कि भारत को आतंक के

विरुद्ध मजबूती से खड़ा रहना चाहिए, लेकिन साथ ही शांति का मार्ग भी नहीं छोड़ना चाहिए। सुप्रिया सुले ने पहलगाम हमले की पृष्ठभूमि में भारत की कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा, हमारे ऊपर अन्याय हुआ, तो कार्रवाई स्वाभाविक थी, लेकिन उसके बाद भारत ने जो संयम और परिपक्वता दिखाई, उसकी दुनियाभर में सराहना की जा रही है। उन्होंने यह भी कहा कि चारों देशों में महात्मा गांधी का गहरा प्रभाव महसूस हुआ। उन्होंने दोहराया कि, मैं किसी सरकार की ओर से नहीं, बल्कि एक भारतीय नागरिक के रूप में सर्वदलीय शिष्टमंडल का

हिस्सा बनी। 'नरेंद्र सरेंडर' वाले बयान पर जानकारी नहीं सुप्रिया सुले से जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के लिए दिए गए 'नरेंद्र सरेंडर' बयान पर प्रतिक्रिया मांगी गई, तो उन्होंने कहा कि उन्हें इस बयान की जानकारी नहीं है, इसलिए उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकतीं। वहीं, जातीय जनगणना पर बोलते हुए उन्होंने कहा, केंद्र सरकार ने आखिरकार जाति आधारित जनगणना का निर्णय लिया है। यह हमारे पार्टी की लंबे समय से मांग रही है और इसके पूरा होने पर हमें खुशी है।

अकरावी ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया में १२ लाख ७१ हजार २९५ विद्यार्थियों की पंजीकरण पहली मेरिट सूची ८ जून को, ११ जून से होंगे कॉलेज में प्रत्यक्ष प्रवेश

मुंबई, विशेष प्रतिनिधि: शैक्षणिक वर्ष २०२५-२६ के लिए महाराष्ट्र राज्य में ११वीं कक्षा (इयत्ता अकरावी) में दाखिले की प्रक्रिया इस वर्ष से केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से की जा रही है। गुरुवार को पंजीकरण की अंतिम तिथि तक कुल १२,७१,२९५ विद्यार्थियों ने इस प्रवेश प्रक्रिया के लिए पंजीकरण किया है। यह जानकारी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षा के प्रभारी संचालक डॉ. श्रीराम पानझाडे ने दी। राज्यभर के कनिष्ठ महाविद्यालयों और उच्च माध्यमिक स्कूलों की पहली सूची में ९,४३५ संस्थाओं ने भाग लिया है, जिनकी कुल प्रवेश क्षमता २१,२३,०४० है। इसमें से १८,९७,५२६ सीटें नियमित फेरी (उ-झ राउंड) के लिए आरक्षित हैं, जबकि २,२५,५१४ सीटें कोटा के तहत हैं। ऑनलाइन पंजीकरण २६ मई से ५ जून २०२५ के बीच <https://mahafycadmissions.in> पर किया गया। इनमें से १२,१५,१९० विद्यार्थियों ने

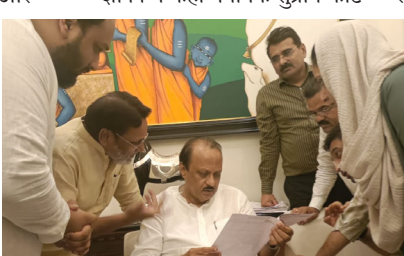
पंजीकरण शुल्क ऑनलाइन जमा किया है। १२,०५,१६२ विद्यार्थियों ने आवेदन पत्र का भाग-१ भरा है। ११,२९,९२४ विद्यार्थियों ने भाग-२ भरकर आवेदन को लॉक किया है। ११,२९,९३२ विद्यार्थियों ने नियमित फेरी (C-PamC\$S>) के लिए आवेदन किया है। ६४,२३८ छात्रों ने इनहाउस कोटा के लिए, ३२,७२१ छात्रों ने मैनेजमेंट कोटा के लिए, और ४७,५७८ छात्रों ने अल्पसंख्यक (मायनॉरिटी) कोटा के लिए आवेदन किए हैं। प्रक्रिया के अनुसार: शून्य फेरी (नशो रैंपव) की मेरिट सूची ८ जून को प्रकाशित होगी। इसके आधार पर ९ से ११ जून के बीच कनिष्ठ महाविद्यालयों में प्रत्यक्ष प्रवेश लिया जाएगा। उ-झ राउंड की मेरिट सूची १० जून को प्रकाशित की जाएगी, और ११ से १८ जून के बीच उ-झ राउंड के अंतर्गत कॉलेजों में प्रवेश होगा।

मस्जिदों पर लाउडस्पीकर के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग नवाब मलिक की अगुवाई में एनसीपी नेताओं ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार से की मुलाकात

मुंबई: महाराष्ट्र में मस्जिदों पर लगे लाउडस्पीकों के खिलाफ जारी पुलिस कार्रवाइयों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की राज्य प्रवक्ता और अनुसक्ति नगर विधानसभा क्षेत्र की विधायक सना मलिक शेख ने उपमुख्यमंत्री अजित पवार से मुलाकात कर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने एक विस्तृत ज्ञापन सौंपते हुए इन कार्रवाइयों को धार्मिक सौहार्द के खिलाफ और एकतरफा बताया।

यह मुलाकात पूर्व मंत्री नवाब मलिक के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल द्वारा की गई, जिसमें पूर्व विधायक ज़ीनाश सिद्दीकी और विधान परिषद सदस्य इदरीस नाइकवाड़ी भी शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने उपमुख्यमंत्री को बताया कि मुंबई, ठाणे, पुणे और औरंगाबाद जैसे शहरों सहित राज्य के

कई जिलों में मस्जिदों पर लाउडस्पीकर को लेकर की जा रही पुलिस कार्रवाइयों असमान और पक्षपातपूर्ण हैं। ज्ञापन में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट



और मुंबई हाईकोर्ट ने लाउडस्पीकर के उपयोग को लेकर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनका पालन मुस्लिम समुदाय कर रहा है। इसके बावजूद केवल मस्जिदों को निशाना बनाकर कार्रवाई की जा रही है, जिससे मुस्लिम समाज में नाराज़गी और असुरक्षा की

भावना उत्पन्न हो रही है। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि जब तक तय डेसिबल सीमा का उल्लंघन साबित न हो, तब तक कोई कार्रवाई न की जाए और यदि कार्रवाई ज़रूरी हो तो पहले संबंधित मस्जिद प्रबंधन से संवाद किया जाए। सना मलिक शेख ने यह भी सुझाव दिया कि उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित की जाए, जिसमें पुलिस और धार्मिक प्रतिनिधियों के साथ मिलकर इस संवेदनशील विषय का स्थायी और संतुलित हल निकाला जाए। प्रतिनिधिमंडल ने आशा जताई कि सरकार जल्द इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएगी, ताकि राज्य में धार्मिक स्वतंत्रता और सामाजिक सौहार्द कायम रह सके।

विश्व पर्यावरण दिवस पर 'महा पर्यावरण' ऐप सहित कई नवाचारों का अनावरण

बांद्रा, मुंबई: संवाददाता विश्व पर्यावरण दिवस २०२५ के अवसर पर महाराष्ट्र राज्य के पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग और महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के संयुक्त तत्वावधान में एक पर्यावरण परिषद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर राज्य सरकार की विभिन्न पर्यावरणीय पहलों और योजनाओं का अनावरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र सरकार के राज्य जलवायु परिवर्तन क्रियावली आराखड़ा माझी वसुंधरा अभियान ६.० टूलकिट, और सल्फर



एमिशन स्कीम जैसी योजनाओं की औपचारिक शुरुआत की गई। इसके साथ ही राज्यभर में प्रदूषण संबंधी समस्याओं और शिकायतों के समाधान हेतु एक नया मोबाइल एप्लिकेशन 'महा पर्यावरण' लॉन्च

किया गया, जो नागरिकों को पर्यावरणीय मुद्दों की रिपोर्टिंग के लिए सशक्त मंच प्रदान करेगा। इस कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार के सांस्कृतिक कार्य, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री एवं मुंबई उपनगर के पालक मंत्री

एडवोकेट आशिष शेलार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष सिद्धेश कदम, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की सचिव जयश्री भोज, तथा मंडल के सदस्य सचिव डॉ. अविनाश ढाकणे सहित कई वरिष्ठ अधिकारी एवं पर्यावरण क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ उपस्थित थे। प्रमुख घोषणाएं: 'माझी वसुंधरा अभियान ६.०' टूलकिट: पर्यावरण संरक्षण की दिशा में जनभागीदारी बढ़ाने का उपकरण। 'सल्फर एमिशन स्कीम': औद्योगिक प्रदूषण पर नियंत्रण हेतु

एक अभिनव पहल। 'महा पर्यावरण' ऐप: नागरिकों के लिए एक तकनीकी प्लेटफॉर्म, जहां वे प्रदूषण से संबंधित समस्याओं की शिकायत दर्ज कर सकेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस के इस अवसर पर इन पहलों के माध्यम से महाराष्ट्र सरकार ने पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में अपने संकल्प को दोहराया है। राज्य सरकार का उद्देश्य न केवल प्रदूषण को नियंत्रित करना है, बल्कि स्थायी एवं हरित भविष्य की ओर बढ़ना भी है।

विशेष संपादकीय गौरक्षा के साथ इंसान कि सुरक्षा भी जरूरी

बीड के साठे चौक पर मासे विक्रेता पर हुए

प्राणघातक हमले ने एक बार फिर हमें एक ज्वलंत प्रश्न की ओर धकेल दिया है - क्या 'गौरक्षा' के नाम पर अब खुलेआम गुंडागर्दी को स्वीकृति मिल चुकी है?

इस पूरे मामले में चिंताजनक बात यह नहीं कि तीन अज्ञात लोगों ने कोयते से हमला किया, बल्कि यह है कि एफआईआर में आरोपी ने शर्ट के अंदर हथियार छिपाया था, यानी यह हमला न केवल सुनियोजित था, बल्कि इसमें 'संदेह' को आधार बनाकर जान लेने की कोशिश की गई। आशंका इस बात की भी है कि यह घटना कोई एकाकी आवेश में हुई प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि हर साल बकरी ईद जैसे धार्मिक अवसरों से पहले बनाई जाने वाली 'डर की स्क्रिप्ट' का हिस्सा है। यह वही स्क्रिप्ट है, जिसमें चंद कथित गौरक्षक, कुछ मांस कारोबारी और पुलिस तंत्र के भीतर के कुछ 'मौन साझेदार' एक डर और दहशत का वातावरण तैयार करते हैं।

सवाल यह है कि: क्या पुलिस हर बार सीसीटीवी फुटेज के भरोसे रहकर हम देख रहे हैं कहकर अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएगी? पीड़ित जब बयान दे रहा हो तो उसे बीच में रोकना किस न्याय का हिस्सा है? अगर हर साल एक ही किस्म की घटनाएं होती हैं, तो खुफिया तंत्र क्या कर रहा है? और सबसे बड़ा सवाल: कानून को हाथ में लेने वालों पर अगर कार्रवाई नहीं होती, तो आम जनता किस पर भरोसा करे? बकरी ईद के मौके पर यह घटना किसी एक व्यक्ति पर नहीं, समाज की धार्मिक आज़ादी और सांप्रदायिक सौहार्द पर हमला है। यह हमला केवल कोयते से नहीं, बल्कि उस संवैधानिक व्यवस्था पर है जिसमें नागरिकों को समान अधिकार का भरोसा दिलाया गया था। जनता से अपील: शांति बनाए रखें, भड़कावे से बचें

हम आम नागरिकों से अपील करते हैं कि वे किसी भी अफवाह, उत्तेजना या उकसावे में न आएं। शांति बनाए रखना हमारी सामूहिक ज़िम्मेदारी है। धार्मिक अवसरों पर शांति और संयम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। प्रशासन से आग्रह: कानून का राज दिखे, सिर्फ लिखा न रहे

पुलिस प्रशासन से अपेक्षा की जाती है कि वह इस हमले की निष्पक्ष और तेज़ जांच करे। आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर न्यायिक प्रक्रिया में लाया जाए। पीड़ित को दबाने के बजाय उसके साथ संवेदनशीलता और निष्पक्षता दिखाई जाए। त्योहारों के समय ख़ास सतर्कता और पेट्रोलिंग की जाए ताकि डर का वातावरण खत्म हो। आज समय आ गया है कि सरकार और पुलिस तंत्र यह स्पष्ट करे कि वे कथित गौरक्षा के नाम पर अराजक तत्वों की छाया से बाहर निकलना चाहते हैं या नहीं। यदि शासन इन घटनाओं को हल्के में लेता रहा, तो यह सामाजिक ढांचे को भीतर से तोड़ देगा। लेकिन अगर आज ठोस कार्रवाई होती है, तो यह संदेश जाएगा - कि भारत का कानून अब भी जिंदा है। क्योंकि सवाल सिर्फ मासेविक्रेता का नहीं, सवाल है संविधान, न्याय और नागरिक सुरक्षा का!

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

तेलगांव रोड से राष्ट्रवादी भवन तक डिवाइडर में रास्ता छोड़ा जाए-खुरशीद आलम की मांग

जिलाधिकारी को सौंपा गया ज्ञापन, विधायक संदीप क्षीरसागर ने की स्थल निरीक्षण

बीड (प्रतिनिधि): बीड शहर के मध्य से होकर गुजरने वाले जालना रोड से तेलगांव रोड होते हुए राष्ट्रीय महामार्ग (हाईवे) का निर्माण कार्य तेजी से जारी है। इस मार्ग पर डिवाइडर बनाए जा रहे हैं, लेकिन कई आवश्यक स्थानों पर रास्ता नहीं छोड़े जाने के कारण नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

इस संदर्भ में खुरशीद आलम के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने बीड के जिलाधिकारी जॉन्सन साहब और बीड के विधायक संदीप भैय्या क्षीरसागर को ज्ञापन सौंपकर डिवाइडर में आवश्यक स्थानों पर रास्ता छोड़े जाने की मांग की है।

ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि बीड से परळी (तेलगांव) रोड के निर्माण के दौरान डिवाइडर डाले जा रहे हैं, और यह मुख्य सड़क शहर के



घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर गुजरती है। शरद पवार राष्ट्रवादी भवन से लेकर तेलगांव नाका और बीड बायपास पुल तक लगभग ५ से ६ किलोमीटर की दूरी में दोनों ओर बड़ी आबादी वाले मोहल्ले, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, विवाह

हॉल, धार्मिक स्थल और शॉपिंग सेंटर्स स्थित हैं। ऐसे में दक्षिण भाग के नागरिकों को उत्तर भाग में आने-जाने में और उत्तर भाग के नागरिकों को दक्षिण भाग में आने-जाने में भारी असुविधा हो रही है।



ज्ञापन में मांग की गई है कि जिस प्रकार होटल शांताई (जालना रोड) से लेकर सह्याद्री होटल (राष्ट्रवादी भवन) तक डिवाइडर में नौ जगह रास्ते छोड़े गए हैं, उसी तर्ज पर राष्ट्रवादी भवन से लेकर बारशी नाका और बीड बायपास

पुल तक भी रास्ते छोड़े जाएं।

इस मांग को गंभीरता से लेते हुए विधायक संदीप क्षीरसागर ने संबंधित अधिकारियों के साथ स्थल निरीक्षण कर मोके का जायज़ा लिया और आवश्यक निर्देश भी दिए।

इस अवसर पर पूर्व विधायक सलीम साहब, मा. सभापती खुरशीद आलम, अभियंता भोपडे साहब, महेश शिंगण, मुफ्ती कौसर साहब, वकील सर, शेख वाजेद, शेख अकील, मुस्ताक भाई, चक्रधर कदम, खदीर इनामदार, आकाश शिंगण, सैय्यद एजाज, शेख मोहसिन, अक्षय शिंगण, शेख कलीम, बंडू खेडकर, मोमिन अज़हर, बालाजी शिंगण, फैय्याज मन्यार, ओम पाटील, शेख फारूक, योगेश भांडवले, मोमिन शहबाज, अजय घोड़के समेत कई नागरिक उपस्थित थे।

थेटेगव्हाण ग्राम पंचायत को संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान अंतर्गत स्व. वसंतराव नाईक विशेष पुरस्कार से सम्मानित

स्वच्छता और ठोस कचरा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए विभागीय स्तर पर मिली पहचान



बीड, ५ जून (प्रतिनिधि):

संत गाडगेबाबा ग्राम स्वच्छता अभियान २०२३-२४ के अंतर्गत छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) विभाग की विभागीय स्तर की पुरस्कार सूची हाल ही में घोषित की गई है, जिसमें बीड जिले के धारूर तालुका की थेटेगव्हाण ग्राम पंचायत को स्व. वसंतराव नाईक विशेष पुरस्कार के लिए चुना गया है। यह निर्णय विभागीय आयुक्त सुरेश चव्हाण की अध्यक्षता में संपन्न विभागीय समिति की बैठक में लिया गया।

थेटेगव्हाण ग्राम पंचायत हाल ही में पहाड़ी पारागांव ग्रुप ग्राम पंचायत से अलग होकर स्वतंत्र रूप में स्थापित हुई है। ग्राम पंचायत की स्थापना के थोड़े ही समय में सरपंच भाऊसाहेब विठ्ठलवार चव्हाण के नेतृत्व में पंचायत ने स्वच्छता और ग्राम विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य कर अपनी अलग पहचान बनाई है।

ग्राम पंचायत द्वारा ठोस कचरा प्रबंधन, सांडपानी निस्सारण (गंदे पानी की निकासी), स्वच्छता मेळावे, स्वास्थ्य शिविर, प्लास्टिक विरोधी अभियान, कचरा वर्गीकरण, कम्पोस्ट यूनिट निर्माण और जनजागरण जैसे कार्यक्रमों को सतत रूप से चलाया गया है, जिससे गांव का समग्र स्वरूप ही

बदल गया है। इससे पूर्व भी थेटेगव्हाण ग्राम पंचायत ने संत गाडगेबाबा स्वच्छता अभियान में जिला स्तर पर द्वितीय क्रमांक प्राप्त किया था, वहीं लोकमत सरपंच अवॉर्ड की प्रतियोगिता में स्वास्थ्य क्षेत्र में जिला पुरस्कार हासिल किया है। यह सफलता केवल स्वच्छता तक सीमित न होकर ग्राम विकास के सभी आयामों को स्पर्श करने वाली साबित हुई है। सरपंच भाऊसाहेब चव्हाण, उपसरपंच जुबेर युसुफ शेख और सभी ग्राम पंचायत सदस्यों ने मिलकर जो सामूहिक प्रयास किए, उससे गांव में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन संभव हो सका। ग्रामवासियों की सहभागिता, पारदर्शिता और नवाचार को पंचायत की कार्यपद्धति में विशेष स्थान दिया गया है।

अब तक थेटेगव्हाण ग्राम पंचायत ने कुल ६ स्पर्धाओं में भाग लिया है, जिनमें से ५ में पुरस्कार प्राप्त किए हैं। इस सम्मान से ग्रामवासियों में हर्ष की लहर दौड़ गई है। सरपंच भाऊसाहेब चव्हाण ने संकल्प लिया है कि आगामी राज्यस्तरीय प्रतियोगिताओं में भी प्रथम क्रमांक प्राप्त कर ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम के रूप में स्थापित किया जाएगा। सरकार की विविध योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के माध्यम से थेटेगव्हाण ग्राम पंचायत एक आदर्श गांव के रूप में उभर रही है।

मोदी सरकार में नई पनडुब्बियों को अब तक मंजूरी क्यों नहीं मिली?: अनंत गाडगिल का सवाल

रिपोर्ट: जमीर काजी, मुंबई
भारतीय नौसेना के पास मौजूद पनडुब्बियों में से लगभग १५ पनडुब्बियों की सेवा अवधि अब केवल ७ से ८ वर्षों तक ही सीमित रह गई है, जबकि ३ से ४ पनडुब्बियों को अगले ५ वर्षों में सेवा से हटाना पड़ेगा। ऐसे गंभीर सुरक्षा हालात के बावजूद नरेंद्र मोदी सरकार ने अब तक एक भी नई पनडुब्बी के निर्माण या खरीद को मंजूरी क्यों नहीं दी? इस सवाल को लेकर कांग्रेस

के प्रवक्ता और पूर्व विधायक अनंत गाडगिल ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है।

उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जुलाई २०२३ में फ्रांस दौर के दौरान स्कॉपीन श्रेणी की ३ पनडुब्बियों के लिए करार की घोषणा की थी। बताया गया था कि यह करार करीब ३०,००० करोड़ रुपये का है और इसे मझगांव डॉक के साथ किया गया है। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी केंद्रीय वित्त मंत्रालय

ने अब तक इस परियोजना को वित्तीय मंजूरी नहीं दी है। क्या यह सही है या झूठ? मोदी सरकार को इसका स्पष्ट जवाब देना चाहिए। सैन्य सशक्तिकरण की घोषणाओं पर सवाल

गाडगिल ने मोदी सरकार पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा, प्रचार और दिखावे में माहिर मोदी सरकार की थाली में जब वास्तविक रक्षा सशक्तिकरण की बात आती है, तो सैन्य बलों को जरूरी हथियार और युद्धसामग्री

के लिए वर्षों तक इंतजार करना पड़ता है। यह गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व काल में जब बैरिस्टर विठ्ठलवार गाडगिल देश के रक्षा उत्पादन मंत्री थे, तब महज दो वर्षों में मझगांव डॉक ने ३ फ्रिगेट और १ पनडुब्बी का निर्माण एवं जलावतरण कर दिखाया था।

रक्षा नीति या अन्देखी? अनंत गाडगिल का कहना है कि देश की सीमाएं सुरक्षित रखने

वाले नौसेना जैसे बलों की जरूरतें प्राथमिकता होनी चाहिए, न कि केवल अंतरराष्ट्रीय यात्राओं और घोषणाओं तक सीमित। उन्होंने सवाल किया कि जब मौजूदा पनडुब्बियों की उम्र पूरी हो रही है, तो रक्षा मंत्रालय और वित्त मंत्रालय अब तक निर्णायक कार्रवाई क्यों नहीं कर पाए? कांग्रेस ने मांग की है कि सरकार इस पर तत्काल स्पष्टीकरण दे और देश की सामरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को राजनीतिक प्रचार से ऊपर रखे।

समृद्धि महामार्ग पर श्वेतपत्रिका जारी हो तो १५ हजार करोड़ का भ्रष्टाचार उजागर होगा-हर्षवर्धन सपकाळ

रिपोर्ट: जमीर काजी, मुंबई
महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने समृद्धि महामार्ग परियोजना पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि यदि इस परियोजना की श्वेतपत्रिका (थहळींशी झरशि) जारी की जाए, तो १५ हजार करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हो सकता है। उन्होंने कहा कि इस परियोजना की मूल लागत ५५ हजार करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर ७० हजार करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।

देवेंद्र फडणवीस सरकार द्वारा समृद्धि महामार्ग के अंतिम चरण के उद्घाटन पर प्रतिक्रिया देते हुए सपकाळ ने कहा, यह परियोजना भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुकी है। अगर सरकार में नैतिकता शेष है, तो

इसे सार्वजनिक किया जाए कि किस काम में कितना खर्च हुआ।

सपकाळ ने आगे कहा कि जैसे घोड़बंदर-भायंदर सुंग और एलिबेटे रोड प्रोजेक्ट में सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ३ हजार करोड़ रुपये के घोटाले का खुलासा हुआ, उसी प्रकार समृद्धि महामार्ग में भी बड़े पैमाने पर घोटाले हुए हैं।

उन्होंने आरोप लगाया कि, देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के करीबी नेताओं ने इस परियोजना से मोटा लाभ कमाया है। '५० खोके एकदम ओके' जैसे राजनीतिक खेल भी इसी भ्रष्टाचार की कोख से निकले हैं।

क्या-क्या मांगी गई जानकारी?

हर्षवर्धन सपकाळ ने समृद्धि महामार्ग

परियोजना पर श्वेतपत्रिका जारी करने की मांग करते हुए निम्न जानकारी को सार्वजनिक करने की बात कही:

प्रत्येक पुल पर कितना खर्च हुआ?

एक किलोमीटर सड़क

निर्माण की लागत क्या रही?

कि सानों को भूमि

अधिग्रहण के बदले कितनी राशि दी

गई?

ठेकेदारों को कितना भुगतान हुआ?

पौधारोपण पर कितने रुपये खर्च

हुए?

टोल से अब तक कितनी वसूली

हुई? निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल

सपकाळ ने कहा कि समृद्धि महामार्ग

की गुणवत्ता बेहद खराब है। कई स्थानों

पर सड़क में दरारें आ गई हैं और निर्माण

शुरू होते ही इस महामार्ग पर दर्जनों

हादसे हुए हैं, जिनमें कई लोगों की जान

गई और कई गंभीर रूप से घायल हुए।

उन्होंने आरोप लगाया कि, यह

प्रोजेक्ट आम जनता की नहीं बल्कि

सत्ताधारी दल के कुछ गिने-चुने नेताओं

की समृद्धि के लिए है।

कांग्रेस ने इस भ्रष्टाचार की जांच

और पोलखोल की मांग की है, ताकि

जनता के पैसे की जवाबदेही तय की

जा सके।

SAPNA TRAVELS

Heavy Parcel Booking
9960828578 / 9156333999

Beed Office
9075868000
7058575575

Online Booking

redBus

www.redbus.in

पे **Paytm**

Beed to Mumbai (panvel-sion-borivali)
Beed to Pune (bhosari-nigdi)

Shivaji Chowk, Near Mahindra showroom, Beed-431122

➡ AC Sleeper

➡ Free Wifi

➡ Free Water bottle

➡ Mobile Charging

➡ CCTV Camera & GPS

➡ Clean & Comfortable bed

Urgent Need for Export

दुबई और दम्माम (सऊदी अरब) के लिए थॉमसन क्वालिटी अंगूर और गणेश या भगवा क्वालिटी अनार की आवश्यकता है।

एक्सपोर्ट क्वालिटी का माल रखने वाले सप्लायर या किसान संपर्क करें।

Tameer Export: MO: 9270574444

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बारशी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafuiddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com